की गई थी। यह अभी भी चालू है; यद्यपि इसे अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस पद्धति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की योजनाओं की भी निगरानी की जाती है।

(ख) किसी राज्य में महत्वपूर्ण विशिष्ट परियोजनाओं की निगरानी राज्य योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। तदनुसार उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं की निगरानी की जाती है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये निधियों का आवंटन

@599. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की उपलब्धियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आबंटित की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) (क) जी, नहीं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, समय-समय पर अंतरमंत्रालयी बैठकों में कार्यक्रम के तहत निष्पादित कार्य की समीक्षा की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के चार घटकों अर्थात्-ग्रामीण ईंधन लकड़ी खेती स्कीम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषाहार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आबंटनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन आबंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के शेष घटकों अर्थात् प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलआपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा उन्नत चूल्हों के लिए आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम घटक	वर्ष 1992-93 के दौरान निधियों का आवंटन (लाख रु०)
(क) ग्रामीण ईंधन लकड़ी खेती स्कीम	2930.00
(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली	252627.00
(ग) पोषाहार	25646.73
(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण	14500.00
जोड़ :	295703.73

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 137, 28 अप्रैल, 1992 से स्थानांतरित।